

## नो-डिटेंशन पॉलिसी समाप्त करने वाला वधियक लोकसभा से पारति

### चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने हाल ही में नशुलक तथा अनविरय शकिषा का अधकिर (दवतीय संशोधन) वधियक, 2017 पारति कर दया है जो ककषा पाँच और आठ में छात्रों को फेल कयि बनिा उनकी प्राथमकि शकिषा पूरी कराने वाली नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्तम करना चाहता है। यह कानून 1.4 मलियिन प्राथमकि वदियालयों के 180 मलियिन से अधकि छात्रों को प्रभावति करेगा।

### प्रमुख बदि

- दरअसल 22 राज्यों ने इस पॉलिसी के कारण शकिषा का स्तर गरिने की बात कहते हुए इसे समाप्त करने की मांग केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद संशोधन का फैंसला लया गया था।
- संशोधति बलि के तहत अब पाँचवीं और आठवीं ककषा में अचछा प्रदर्शन नही करने वाले छात्रों को एक और मौका दया जाएगा। इस परीकषा में भी अगर छात्र स्तरीय प्रदर्शन नही कर पाते हैं तो उन्हें फेल घोषति कर दोबारा उसी ककषा में प्रवेश दया जाएगा।
- इस वधियक के पास होने पर प्राथमकि शकिषा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।
- मानव संसाधन वकिस मंत्रालय के मुताबकि, चार या पाँच राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्य नो-डिटेंशन पालिसी खत्तम करने के पक्ष में हैं।
- आरटीई संशोधन वधियक के अनुसार, छात्रों को परीकषा उत्तीर्ण करने के दो मौके दये जाएंगे और अगर वे दोनों प्रयासों में वफिल हो जाएंगे तो उन्हें फेल घोषति कर दोबारा उसी ककषा में प्रवेश दया जाएगा।
- छात्रों के साथ भेदभाव नही कया जाएगा, लेकिन अगर वे सीखने के स्तर तक पहुँचने में नाकाम रहते हैं तो स्कूल के अधकिारयों के पास छात्रों को उसी ककषा में प्रवेश देने के अलावा कोई वकिल्प नही होगा।
- हालाँकि, बलि में राज्यों को स्कूल, ज़ाला या राज्य स्तर पर परीकषाओं का चयन या संचालन करने के लये नो-डिटेंशन पालिसी जारी रखने की अनुमति देने का प्रावधान है।
- अप्रैल 2010 में आरटीई अधनियम की शुरुआत के बाद से पहली से लेकर आठवीं ककषा तक कोई भी छात्र फेल नही हुआ था, लेकिन इस अभ्यास ने शकिषा के खराब स्तर के लये इसे आलोचना का शकिर बना दया।
- गैर-लाभकारी संगठन 'प्रथम' द्वारा प्रकाशति ग्रामीण भारत के लये शकिषा रिपोर्ट की वार्षकि स्थति (ASER) के अनुसार, पाँचवी ककषा के सभी छात्रों का अनुपात जो ककषा दो के स्तर की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते थे, 2014 में 48.1% से गरिकर 2016 में 47.8% हो गया। अंकगणति और अंगरेज़ी वषिय में भी यही स्थति देखी गई।
- भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत वभिन्न दलों के कई सांसदों ने छात्रों के खराब प्रदर्शन के लये शकिषकों पर जवाबदेही तय करने की मांग की।
- शकिषा के अधकिर के मौजूदा प्रावधान के अनुसार, छात्रों को 8वीं ककषा तक फेल होने के बाद भी अगली ककषा में प्रवेश दे दया जाता है, इसे ही हम 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' के नाम से जानते हैं।

इस बारे में अधकि जानकारी के लये दये गए लकि पर क्लिक करें :

⇒ [नो-डिटेंशन पॉलिसी में प्रस्तावति बदलाव का मूल्यांकन](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/lok-sabha-passes-bill-allowing-detention-of-children)